>

Title: Need to enhance the food grain storage facilities in the country.

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की घोषणा की ओर अगर ध्यान न दिया गया तो वर्ष 2011 में विकासशील देशों में अनाज मंहगे हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में 75 फीसदी लोगों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं जो भूखे या आधे पेट खाना खाकर काम चला रहे हैं। क्योंकि महंगाई इतनी अधिक हो गयी है कि वे आवश्यक खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि जिस देश में 70 से 80 फीसदी जनता प्रति दिन 20 रुपए खर्च करने की स्थिति में हो तो वह भला भरपेट भोजन कैसे कर सकती है।

वहीं दूसरी ओर देश में खाद्यान्न सड़ रहे हैं और मा. सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने व जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर भी सरकार नीतिगत मामले की बात कह कर आवश्यक कदम नहीं उठाती।

खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए देश में सरकारी क्षेत्र में मात्र 525 कोल्ड स्टोरेज हैं जो हर तरह से अपर्याप्त हैं फिर भी सरकार खाद्यान्नों की स्टोरेज क्षमता में इजाफा करने में गभीर नहीं दिखती है।

देश के दूर-दराज क्षेत्रों को छोड़ दें और देश की राजधानी की बात करें तो हर वर्ष तकरीबन एफ.सी.आई. के गोदामों में 10 करोड़ रुपए का अनाज बरसात में भीगकर बर्बाद हो जाता है।

मेरा आग्रह है कि भूखों को पर्याप्त खाद्यान्न मिले और महंगाई पर अंकुश लगा रहे इसके लिए आवश्यक है कि खाद्यान्नों की स्टोरेज क्षमता को सरकार अविलम्ब बढ़ाए जिससे खाद्यान्न सुरक्षित रहे और जरूरत के समय जनता के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराय जा सके।